Universal Research and Academic Journal
E-ISSN: 2584-2838
(Peer Reviewed, Refereed and Multidisciplinary Journal)
Universal Research and Academic Journal
Volume: 02, Issue: 02, (Feb-2026), pp: 21-31
Received: 11th February, 2026 *Accepted:* 24th February, 2026 ©URAJ: 2026/02/021/031/003

बारां जिले भूमि उपयोग एवं कृषि आधारित उद्योग

Neha Sharma[1], Dr. Renu[2]

[1]Research Scholar, Faculty of Humanities & Social Studies, Dr. K N Modi University, Newai, Tonk, Rajasthan, India,
[2]Assistant Professor, Faculty of Humanities & Social Studies, Dr. K. N. Modi University, Newai, Tonk Rajasthan

सारः बारां जिले के भूमि उपयोग के अन्तर्गत परिवर्तन की प्रकृति पायी गयी है, इसमे सुविधाओं एवं सकारात्मक कारकों ने वृद्धि को इंगित किया है। जिससे क्षेत्र की विशेष पहचान बनी है वही दूसरी और प्रतिकूल कारकों एवं नकारात्मक पहलूओं के कारण कमी भी हुई है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है, इसमें विशेष रूप से वन क्षेत्रों में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। जिससे पर्यावरणीय सन्तुलन बना रहे साथ ही कृषि पर दबाव कम हो और वन आधारित उद्योगों का विकास भी आवश्यक है। इसी प्रकार कृषि योग्य भूमि के विभिन्न वर्गों को नियोजित करने की आवश्यकता है जिससे भूमि उत्पादन क्षमता बनी रहे तथा कृषि की गहनता को स्थिर रखते हुए कुषि भूमि को प्रबन्धन भी आवश्यक है। जिसमें कृषि एवं ग्रामीण रोजगार को विकसित करना आवश्यक है। जिससे बारां जिले का सन्तुलित विकास हो सकता है।

शब्दकोशः भूमि उपयोग, प्रवृत्ति, प्रबन्धन, कृषि, प्रतिशत, कमी वृद्धि, फसले, तालिका

प्रस्तावनाः बारां जिले में भूमि उपयोग की गत्यात्मकता रही है। यहां के भूमि उपयोग की परिवर्तनशील प्रवृत्ति में आधुनिक कृषि आदानों का प्रभाव रहा है अतः यहां भूमि उपयोग की गत्यात्मकता का अध्ययन करने का प्रयास रहा है। जिससे अलवर जिले के भूमि उपयोग के नियोजन एवं प्रबन्धन युक्त कर सर्वाधिक उपयोगी बनाने में सहयोग प्राप्त होगा । धरातल पर विद्यमान संसाधनों में मानव व भूमि संसाधन बहुत ही उपयोगी घटक है । यह समय की आवश्यकताओं एवं क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील होते रहे है। भूमि संसाधन पर मानव अपनी समस्त आर्थिक क्रियाएँ सम्पन्न करता है। जिसमें भूमि उपयोग की व्यापकता रहती है, जिसमें कृषि फसलें एवं कृषि उत्पादन होता है, जो कृषि विकास को प्रभावित

© **Corresponding Author:** Neha Sharma

करते है, जिसमें कृषि भूमि में भूमि उपयोग नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । यथा मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ा और उसका सम्पूर्ण जीवन भू–उपज पर आश्रित है अतः इसके बदलते स्वरूप का आधार प्रवास को निधार्रित करता है ।

अध्ययन क्षेत्रः बारां जिला 24˚24श से 25˚26श उत्तरी अक्षांश और 76˚12श से 77˚26श पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है (चित्र 1)।

यह राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमा पूर्व, दक्षिण और दक्षिण–पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले और इसके दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान के मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः लगभग 110 किमी और 120 किमी, जिले की स्थानिक सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

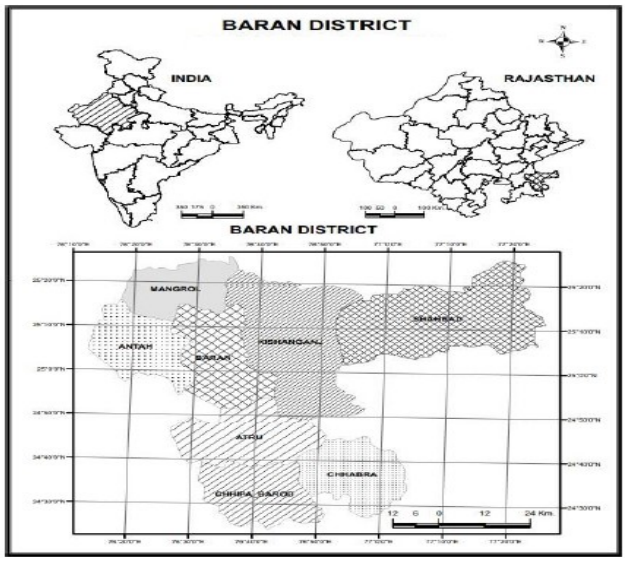

चित्रः 1 राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र का मानचित्र

शोध उद्देश्यः किसी भी शोध अध्ययन कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्य आवश्यक होते है जो प्रभावी होते है, प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार रहे है–

- भूमि उपयोग के को प्रस्तुत करना ।
- कृषि आधारित उद्योग को प्रस्तुत करना ।
- भूमि उपयोग परिवर्तन के कारकों का अभिज्ञान।

शोध परिकल्पनाएँः

परिकल्पनाएँ किसी शोध अध्ययन कार्य को सम्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है । इस शोध कार्य में अध्ययन कर्त्ता की निम्न परिकल्पनाऐं रही है–

- जनांकिकीय वृद्धि का सर्वाधिक भार भूमि उपयोग क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- कृषि विकास एवं कृषि विस्तार के लिए भूमि उपयोग नियोजन बहुत आवश्यक है।
- आधुनिक कृषि आधारित उद्योग को प्रस्तुत करना ।

आँकड़ों के स्रोतः प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के लिए आँकड़ो का सहयोग लिया है ये आँकड़े द्वितीयक रहे है जो सरकारी संस्थाओं द्वारा संकलित किये गये है। जो निम्न प्रकार है–

शोधविधिः

- भारतीय जनगणना 2011 जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।

- आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
- जिला कार्यालय बारां, राजस्थान ।
- जिला जनगणना प्रतिवेदन 2001 व 2011

प्रस्तुत शोध पत्र की पूर्णता व शुद्धता के लिए प्राप्त आकड़ों को तालिका में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिशत मान भी दिया गया है। इसमें आधार वर्ष व चालू वर्ष के अन्तराल की गणना प्रस्तुत की गई है तथा इनके परिणामों के अध्ययन को क्रमबद्ध किया गया है।

भूमि उपयोग प्रतिरूपः भूमि उपयोग का अध्ययन कृषि सांख्यिकी द्वारा तकनीकी कमेटी ने वर्ष 1948 में खाध्य व कृषि मंत्रालय के सहयोग से विकसित भूमि उपयोग 9 उपभागों में बांटा है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद भूमि, चारागाह, वन आदि के अनुसार वास्तविकता को प्रदर्शित करता है । ये आंकडे क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग के विश्लेषण में अति आवश्यक होते है–

- कुल भौगोलिक क्षेत्रा का प्रतिशत
- वास्तविक बोया गया क्षेत्रा का प्रतिशत
- स्रोतः आर्थिक सांख्यिकीय निदेशालय, जयपुर ।

अध्ययन क्षेत्र बारां जिले का भूमि उपयोग कृषि उत्पादन एवं कृषि आधारित उद्योग के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कृषि पद्धति तथा फसलों की उत्पादन वृद्धि की योजनाओं में भूमि उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा तथा परिवर्तन का अध्ययन बहुत की उपयोगी व आवश्यक होता है, भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप ने कृषि विकास को प्रभावित किया है।

जनसंख्या वितरणः भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक और तकनीकी विशेषताओं के साथ–साथ उनके और जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व जैसे अन्य कारकों के बीच अंतर, सभी का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या एक गतिशील कारक है जो स्थिर न होकर समय के साथ बदलती रहती है। संक्षेप में, जनसंख्या में उतार–चढ़ाव होता है, कभी बढ़ती है तो कभी गिरती है। जनसंख्या भूगोल अपने स्वभाव से ही अंतः विषयक है। आर्थिक विकास जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं और ताकतों से प्रभावित होता है। मानव संसाधन हर स्थान के आर्थिक विकास की कुंजी है। जनसांख्यिकीय चर का व्यापक अनुसंधान एक विशिष्ट क्षेत्र में किया जाता है। जनसंख्या की मात्रा में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण और मात्रा और गुणवत्ता प्रकार के साथ अन्य संसाधन जैसी चीजें शामिल हैं। ज्ञान, प्रतिभा, आयु समूह आदि के आधार पर जनसंख्या की विशेषताएं भिन्न–भिन्न हो सकती हैं(एकनाथ)।

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनसंख्या	
		2011-12	2021-22
1	मांगरोल	106963	122313
2	अन्ता	120038	138761
3	बारां	213555	251032
4	अटरू	149959	169125
5	किशनगंज	166864	205812
6	शाहबाद	142061	186516
7	छबड़ा	152429	189857
8	छीपाबड़ौद	170886	202860
कुल		**12,22,755**	**14,66,276**

तालिका 1: तहसीलवार जनसंख्या वितरण 2011 और

2021 (Source: 2011 District Census Handbook, 2021)

जिले की कुल जनसंख्या 12,22,755 (2011) थी। जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग बारां तहसील में है तथा सबसे छोटा भाग मांगरोल में है। जिले में निवासियों की संख्या बढ़कर 14,66,276 (2021) हो गई (तालिका 1)। पुनः, बारां तहसील में कुल जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, जबकि मांगरोल तहसील में सबसे कम अनुपात है।

बारां तहसील में लगातार जनसंख्या का उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया है। सामाजिक–आर्थिक कारणों से, मुख्य रूप से विभिन्न शैक्षिक केंद्रों की सघनता, विनिर्माण, थोक और खुदरा वाणिज्य, वित्त और व्यवसाय, सरकारी और चिकित्सा सेवाओं आदि जैसी आर्थिक गतिविधियाँ बारां तहसील के घने जनसंख्या वितरण का कारण हैं।

भूमि उपयोग पैटर्नः कृषि भूमि उपयोग का तात्पर्य विभिन्न उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए भौगोलिक क्षेत्र के प्राथमिक उपयोग से है। भूमि उपयोग किसी दिए गए समय और स्थान पर एक विशिष्ट बिंदु पर सभी विकसित और खाली भूमि का सतही उपयोग है। यह कृषि विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतक है। भूमि उपयोग विश्लेषण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो क्षेत्रीय योजना और विकास के साथ–साथ भविष्य के अभिविन्यास के लिए उचित दिशानिर्देश प्रदान करता है। भूमि उपयोग पैटर्न में भूमि के प्रकार और विभिन्न उपयोगों के तहत कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, शामिल है।

भूमि मानव समाज का बुनियादी संसाधन है और भूमि उपयोग एक निश्चित समय और स्थान पर विशिष्ट बिंदु पर सभी विकसित और खाली भूमि का सतही उपयोग है। यह मुख्य रूप से मानव समाज की आवश्यकताओं को बुद्धिमानी से और प्रभावी ढंग से संतुष्ट करने के लिए उनकी मौलिक उपयोगिता को पहचानने और समझने के लिए कुछ समान विशेषताओं के आधार पर भूमि के विभिन्न वर्गों की एक व्यवस्थित व्यवस्था है।

भूमि का उपयोग स्थलाकृति जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मिट्टी और जलवायु के साथ–साथ मानवीय कारकों जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र की भूमि पर कब्जे की अवधि और जनसंख्या की तकनीकी प्रगति। भौतिक और मानवीय कारकों की निरंतर परस्पर क्रिया के कारण भूमि उपयोग में ये स्थानिक और लौकिक अंतर।

क्रम संख्या	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	349143	49.92
2	भूमि को गैर-कृषि उपयोग में लाया गया	32881	4.70
3	वर्तमान परती भूमि	7986	1.14
4	अन्य परती भूमि	13586	1.94
5	वन	217928	31.15
6	बंजर एवं अनुपयोगी भूमि	31939	4.57
7	बंजर एवं कृषि योग्य भूमि	12048	1.72
8	झाड़ियों और बगीचों के अंतर्गत क्षेत्र	183	0.03
9	चारागाह/चारागाह भूमि	33767	4.83

तालिका 2: बारां जिले का भूमि उपयोग पैटर्न

2015–16 के दौरान बारां जिले का कुल सूचित क्षेत्रफल 699461 हेक्टेयर था (तालिका 2)। सामान्य तौर पर, भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि के लिए समर्पित है, लेकिन काफी भूमि का उपयोग गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। 2015–16 के दौरान जिले का शुद्ध बोया गया क्षेत्र (एनएसए) 349143 हेक्टेयर था। यह जिले के कुल सूचित क्षेत्रफल का 49.92 प्रतिशत है। तालिका से पता चलता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बाद भूमि उपयोग की अगली प्रमुख श्रेणी वनों के उपयोग के लिए रखा गया क्षेत्र है जिसमें लगभग 217928 हेक्टेयर (31.15:) भूमि शामिल है, इसके बाद चारागाह भूमि (33767) हेक्टेयर और गैर–कृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि (32881 हेक्टेयर) है।

कृषि विशेषताएँ: बारां जिला राजस्थान के प्रमुख कृषि जिलों में से एक है। शुद्ध दर्शाए गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 349143 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल सूचित क्षेत्र का 49.92 प्रतिशत भाग खेती के अंतर्गत है। यह जिला अच्छी मिट्टी, पर्याप्त भूजल से संपन्न है और यहां तीन फसल उगाने के मौसम होते हैं यानी रबी और खरीफ दोनों ही जिले की मुख्य फसलें हैं। जिले में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी और काली डुमट मिट्टी उपजाऊ हैं। यह जिला राज्य में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। काली सिंध, चंबल और परवन नदियों का क्षेत्र मंगरोल तहसील की पश्चिमी सीमा बनाते हुए उत्तर की ओर बहती है। अंता, मांगरोल, अटरू जिले और बारां तहसील बहुत उपजाऊ हैं, जहां उत्तर–पश्चिमी कोना आसपास की पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ झालावाड़ जिले का है और चंबल के ठीक नीचे दारा तक जाता है। रबी मौसम के दौरान क्षेत्र की प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का, कपास, सरसों, चना, अलसी और धनिया हैं। क्षेत्र में लगभग 26 प्रतिशत फसल क्षेत्र सिंचित है। हाल ही में सोयाबीन जिले में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में उभरी है।

गेहूं एवं धनिये की रबी फसल के उत्पादन में जिला शीर्ष पर है। बारां जिले की मुख्य फसलें चावल, मक्का, उड़द, ज्वार आदि हैं। बारां में तिल और सोयाबीन का उत्पादन राज्य में प्रसिद्ध हो रहा है। रबी मौसम के दौरान क्षेत्र की प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का, कपास, सरसों, चना, अलसी और धनिया हैं। प्रमुख सब्जियों में आलू, टमाटर, प्याज, खीरा, मिर्च, भिन्डी, टिण्डा, लाला प्रमुख हैं।

प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादनः ख़रीफ़ सीज़न (जुलाई–अक्टूबर) में जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फ़सलें ज्वार, मक्का, हैं दालें, मूंगफली और सोयाबीन। रबी (नवंबर–मार्च) फसलें गेहूं के रूप में उगाई जाती हैं जौ, चना, अलसी, सरसों और धनिया। धनिया और सोयाबीन प्रमुख हैं

जिले की फसलें: बारां जिला में 72.66ः मानव कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र जिले की कुल आबादी का 32.85ः आजीविका प्रदान करते हैं। केस करना जरूरी हैद्य भूमि उपयोग, सिंचाई सुविधा, फसल उत्पादन, पशुधन, डेयरी, खनिजों और वन उपज आदि।

प्रमुख फसलें:

- ख़रीफ़ सीज़न (जुलाई–अक्टूबर) में जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फ़सलें ज्वार, मक्का, दालें, मूंगफली और सोयाबीन।
- रबी (नवंबर–मार्च) फसलें गेहूं के रूप में उगाई जाती हैं
- जौ, चना, अलसी, सरसों और धनिया। धनिया

वन संसाधनः 2240 वर्ग किमी में वन क्षेत्र लगभग 31ः है। 2,16,790 हेक्टेयर हैंद्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6,99,461 के मुकाबले वन क्षेत्र के रूप में कवर किया गया है। यह जिला समृद्ध है वन बेल्ट. इस जंगल में पाए जाते हैं यह बीड़ी बनाने का मुख्य संसाधन है। अन्य महत्वपूर्ण लघु वन घास, गोंद, शहद, मोम, बांस, चिरौंजी आदि उत्पाद हैं। वनों का निम्न में विभाजन किया गया है।

S. No	Category	Area in hectare
1	Reserved Forest	213422.07
2	Unclassified Forest	666.34
3	Total	214088.41

तालिका 3ः वनों का निम्न में विभाजन (Source: District Census Handbook Part XII-A, Baran , Rajasthan)

कृषि पर आधारित रोजगारः

1. संभावित वस्तुओं का निर्यातः बारां जिला. कृषि उत्पादों के लिए समृद्ध है. सोयाबीन का उत्पादन होता है, लहसुन, धनिया, गेहूं आदि लहसुन का पेस्ट, पाउडर, फ्लेक्स, धनिया होता हैद्य कोटा से यह लगभग 75 कि. मी. है। निर्यात करने की संभावना. ये वस्तुएं राज्य से बाहर निर्यात की जाती हैं।

पोषक पदार्थों की तरह फलों एवं सब्जियों का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल प्रचलित सब्जियों के अलावा कई नई तरह की सब्जियाँ आ गई हैं। जिनका मूल्य अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा है इनमें ब्रोकली, चाइनीज़, पत्तागोभी, बटनगोभी, लाल पत्ता गोभी, विभिन्न रंगों वाली शिमला मिर्च, हाइब्रीड, टमाटर प्रमुख हैं। इनकी माँग घरेलू बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में बहुत है। भारतीय उपभोक्ता प्रसंस्कृत फलों की तुलना में ताजे फल अधिक पसन्द करते हैं। प्रसंस्कृत उत्पादों की अपेक्षा ताजे फलों व सब्जियों के प्रयोग के कारण माँग अधिक है परन्तु फिर भी यह सत्य है कि फलों एवं सब्जियों का बहुत सा हिस्सा प्रसंस्करण संरक्षण एवं उचित भण्डारण के अभाव में नष्ट हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि फलों एवं सब्जियों का सही संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रसंसीकरण करके उसे देशी एवं विदेशी बाजारों में बेचकर ग्रामीण बेरोजगार घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बाजार में फलों की माँग अधिक है जिनसे देश के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा ही नहीं प्राप्त की जा सकती बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा किये जा सकते हैं। जिन ताजे फलों के निर्यात की अधिक सम्भावनायें मानी जाती हैं उनमें आम, अंगूर, केले, लीची और विजातीय फलों में अनार सपोटा आदि शामिल हैं। इस कार्य को समूह एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर किया जाये तो इसमें बैंक भी आर्थिक मदद प्रदान करता है।

2. बीज उत्पादन पर आधारित रोजगारः कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिए वर्तमान में मौजूद तकनीक और भविष्य में विकसित होने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बीजों की आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता अति आवश्यक है। आज आधुनिक कृषि के लिए उन्नत किस्म के बीज कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं और उत्पादन बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में बीजों के महत्व को स्वीकार करते हुए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम और 1969 में ष्भारतीय राज्य फार्म निगमष् की स्थापना की। इसका उद्देश्य विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करना था । सच यह भी है कि आज देश में उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता भी अधिक है । परन्तु देश में आवश्यकता के दसवें हिस्से का भी बीज नहीं बन रहा है। किसान उन्नत बीज की जगह केवल अपने घर पर उपलब्ध बीज की ही बुआई कर रहा है। पर परिस्थिति में यदि गाँव के पढ़े लिखे बेरोजगार अपना संगठन बनाकर जमीन को लीज़. या शिकमी पर लेकर सामूहिक बीज बनाने का कार्य करें तो आधुनिक प्रजातियों के उन्नत बीज किसानों को प्राप्त हो सकते हैं। बीज उत्पादन का क्षेत्र और सम्भावनायें काफी व्यापक हैं, साथ ही ग्रामीण बेरोजगारों को घर पर आकर्षक रोजगार एवं आय प्राप्त करने का साधन बना सकता है।

3. दुग्ध उत्पादन पर आधारित रोजगारः पशुपालन का ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान है। देश में दुग्ध विकास की असीम सम्भावनायें हैं, बेरोजगार युवक डेयरी क्षेत्र में आगे आकर खूब तरक्की कर सकते हैं। शर्त यह है कि वे परंपरागत तरीकों के स्थान पर बेहतर व उन्नत ढंग से डेयरी की व्यवस्था करें तो इसमें लाभ ही लाभ है आज देश में लगभग 915 लाख टन दूध का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। हमारे देश दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन में 14: की हिस्सेदारी के साथ दूध का बड़ा उत्पादक देश है। यदि ग्रामीण बेरोजगार पशुपालन से दूध उत्पादन का व्यवसाय करें तो इससे घर बैठे रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इससे अच्छी आय अर्जन कर सकेंगे। इसके लिए गाँव में सहकारी समूह बनाकर उसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक का कार्य उसी सहकारी समूह द्वारा किया जाये, जिससे बिचौलियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो। इस सम्बन्ध में विपणन में होने वाले आवागमन व्यय तथा कार्यकर्ताओं के वेतन पर जो भी खर्च होता है उसे सहकारी समूह वहन करता है अब समिति की पूरी आय से व्यय को घटाकर शेष धनराशि दुग्ध उत्पादकों को सीधे प्राप्त हो जातीहै। इसी तरह दुग्ध के विभिन्न उत्पाद बनाकर बेरोजगारों को अच्छा लाभ मिल सकता है।

4. कुक्कुट व मधुमक्खी पालन पर आधारित रोजगारः कुक्कुट व मधुमक्खी पालन किसानों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इससे कम समय व कम व्यय पर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, बेहतर मार्ग निर्देशन मिलने पर हमारा ष्मॉस+ चूज्ञा + अण्डा उद्योग देश के फलते फूलते कृषि उद्योग में शुमार हो सकता है। देश में सोयाबीन और मक्का उत्पादन बहुत है जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मुर्गियों के दाने के रूप में किया जा सकता है। इससे आनेवाले वर्षों में कुक्कुट उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार मधुमक्खी

पालन से किसानों को शहद तो प्राप्त होता ही है साथ ही इससे मोम भी प्राप्त होता है। वैसे तो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भारत में प्राचीन काल से हो रहा है फिर भी देश में शहद उत्पादन एवं मोम विदेशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में प्रति छत्ता शहद 5 किग्रा0 प्राप्त होता है जबकि अमेरिका में शहद प्रति छत्ता 25–30 किग्रा० निकलता है। यह बात तो सत्य है कि कुक्कुट व मधुमक्खी पालन के व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है। यदि गाँव में बेरोजगार इसे मिशन मानकर तथा रख–रखाव का वैज्ञानिक तरीका अपनाकर इसे रोजगार के रूप में अपनाये तो इससे आकर्षक आमदनी घर बैठे कमाई जा सकती है। इस व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थायें ऋण देने में सदैव तत्पर रहती हैं।

5. बागवानी पर आधारित रोजगारः भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी और मौसम पाया जाता है। कई प्रकार की जलवायु और पर्यावरण सम्बन्धी विविधता मिलती है जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार के फलों एवं सब्जियों के अलावा फूलों की खेती वर्तमान में एक अच्छा रोजगार माना जा रहा है। बागवानी पर आधारित व्यवसाय में गुलाब, सेवन्ती, गेंदा, रजनीगन्धा, बेला, मोगरा, ग्लेडियोलाई विभिन्न प्रकार के देशी व विदेशी मौसमी पौधों तथा सजावटी कैक्टस, क्रोटन, तथा बोर्नसाई वाले पौधों का व्यवसायिक उत्पादन काफी लाभदायक माना जा रहा है। इस सम्बन्ध में अच्छी सरकारी संस्थायें आई0आई0एच0आर0, बंगलौर, आई0ए0आर0आई0 नई दिल्ली से अच्छी प्रजातियों की बागवानी हेतु बीज अथवा पौधे प्राप्त कर नर्सरी बनाने का व्यवसाय निःसन्देह ग्रामीण बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

6. वन औषधियों पर आधारित रोजगारः भारत में जड़ी बूटियों से औषधियाँ प्राप्त कर अनेक रोगों का उपचार करने का उल्लेख प्राचीन काल से ही मिलता है। सदियों से जड़ी बूटियाँ विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त की जाती रही हैं। अनेक जड़ी–बूटियों का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। आज विश्व बाजार में भी आयुर्वेदिक दवाइयों ने अपनी पहचान बना ली है। आज के बदलते परिदृश्य में वन औषधियों माँग एवं विश्व बाजार में निर्यात बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आज चीन जैसा राष्ट्र वन औषधियों को बेचकर विश्व बाजार में अग्रणी निर्यातक देश बन गया है जबकि भारत में औषधीय पौधों की सर्वाधिक विविधता होने के बावजूद हम चीन से काफी पीछे हैं। आज देश में बहुत सी संस्थायें, जैसे डाबर, हिमालया, झण्डू, वैद्यनाथ, हिमानी आदि वन औषधीय पौधों व उनसे प्राप्त उत्पादों को खरीदने के लिए तत्पर हैं। इसमें अवूबगंधा, तुलसी, ईसबगोल, बच, सफेद मूलसी, मुश्कदाना, सोनामुखी, कमलगट्टा, कालमेघ, लेमनग्रास, सिनकोना, सतावर, सदाबहार, आदि औषधीय एवं सुगन्धित पौधों को बड़े पैमाने पर लगाकर ग्रामीण बेरोजगार इसे अपनाकर रोजगार का साधन बना सकते हैं।

7. कृषि उपकरणों पर आधारित रोजगारः मशीनी खेती से श्रम और समय की बचत होती है। इसीलिए दीर्घकालीन कृषि विकास के लिए यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जुताई के तरीकों, सिंचाई पद्धति व फसल

कटाई और गहाई की मशीनों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए अनुसन्धान की जरूरत है। इस बदलते दौर में खेतों की जुताई, गुड़ाई एवं कटाई आदि के लिए आज आधुनिक मशीन देश के सभी किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। यदि कृषि यन्त्रों को बनाने के लिए ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर निर्माण हेतु डिस्क, हैरो, कल्टीवेटर, रोटा वेटर प्लाऊ जुताई के लिए तथा फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर, रीपर, एवं सीड कम फर्टी ड्रिल, फरोरिज बैंड, प्लाटर, तिफन आदि को बनाकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इससे कृषकों को सभी प्रकार के कृषि यन्त्र गाँव में उपलब्ध होंगे और बेरोजगारों को रोजगार अर्थात् एक तीर से दो शिकार ।

8– लघु मिलों पर आधारित रोजगारः दलहन तिलहन एवं चावल की खेती व्यवसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है इसलिए लघु मिलों के लिए जहाँ अल्प पूँजी की आवश्यकता होगी वहीं देश में रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायनवादी संस्कृति में भी कमी आयेगी । वर्तमान में ग्रामीण बेरोजगारों का महानगरों की ओर पलायन रोकने एवं रोजगार प्राप्ति के लिए गाँव में ही दलहन से दाल, निकालने के लिए दाल मिल की स्थापना तिलहन से तेल निकालने के लिए तेल मिल की स्थापना, धान से चावल निकालने के लिए चावल मिल की स्थापना, गेहूँ से आटा बनाने के लिए बड़े स्तर पर फ्लोर मिल तथा छोटे स्तर पर आटा चक्कियों की स्थापना की जाती है। यह अपने आप में लाभप्रद व्यवसाय है। इससे ग्रामीण बेरोजगारों को गाँव में ही रोजगार एवं आय प्राप्त करने के अच स्रोत स्थापित हो सकते हैं। इस हेतु स्वयं सहायता समूह बनाकर वित्तीय संस्थाओं व खादी बोर्ड से ऋण लेकर भी आसानी से चलाया जा सकता है।

9. जैविक कृषि पर आधारित रोजगारः जैविक कृषि की अवधारणा प्रादुर्भाव और विकास के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात होता है कि भारत के किसानों के लिए जैविक कृषि की अवधारणा कोई नई नहीं है। वास्तव में जैविक कृषि वही है जो कि हमारी मिट्टी और जलवायु के अनुसार हो और हमारे पास उपलब्ध संसाधनों द्वारा हो । वनस्पतियों के अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाकर तैयार किये गये खाद को कम्पोस्ट खाद्य या हरी खाद कहा जाता है कृत्रिम पर्यावरण में केचुओं का पालन–पोषण वर्मीकल्चर कहलाता है।

केचुंओं द्वारा निर्मित खाद किसी अन्य खाद से अधिक लाभदायक होती है। जैविक कृषि एक प्रकार से प्राकृतिक खाद्य चक्र को दोबारा कायम करना है। कुछ जीव जैसे– मधुमक्खी, केचुंआ, मेंढक, कीट–भक्षी चिड़ियाँ आदि का खेत में आना यह संकेत है कि जैविक कृषि का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है। कृषि केवल मनुष्य और फसल के बीच का रिश्ता नहीं है वरन् प्रकृति में पाये जाने वाले प्रत्येक जीव का इसमें सहयोग और उत्पादन में हिस्सा भी होता है। जैविक खाद्य के इस व्यवसाय को अपनाकर ग्रामीण बेरोजगार विपणन की नीतियाँ बना रोजगार एवं आय प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्षः भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में कृषि आधारित उद्योग–धन्धों को अपनाकर कृषि व्यवसाय एवं रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। कृषि को

प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार मूलक बनाने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक और निजी निवेश भी आवश्यक हैं। इससे कृषि प्रयोग के नये–नये तरीकों का ज्ञान सही दिशा एवं स्पष्ट मार्गदर्शन किसानों को मिलने लगेगा, साथ ही किसानों को सही खाद्य, बीज, पौध आदि उपलब्ध होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनायें बनाई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत करने और रोजगार के नये–नये अवसरों में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है।

भारतीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यदि देश का विकास करना है तो कृषि एवं रोजगार को वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक ताकत के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। पहले हमें अन्दर से मजबूत होना पड़ेगा, यानी उस भारत को खुशहाल बनाना होगा जहाँ 68 से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जिसे ग्रामीण भारत के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण बेरोजगारों की दयनीय दशा में सुधार कर इन कमियों का निराकरण करके ग्रामीण रोजगार व कृषि विकास की इन महत्वकांक्षी योजनाओं व कार्यक्रमों से अपेक्षित परिणाम होने की सम्भावनायें बढ़ सकती हैं। कृषि में रोजगार के संवर्द्धन के पश्चात् ही गाँवों में रोजगार और विकास की गंगा बह सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति निर्माता, कृषि समुदाय संगठन, स्वयंसेवी संगठन और कृषि वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। कृषि में प्रगति के बिना समग्र विकास की कल्पना एक मृग तृष्णा बनकर रह गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व अल्पबेरोजगारी की समस्या और भी भयानक है, यहाँ सबसे भीषण समस्या अल्पबेरोजगारी की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषीय अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि आधारित उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि आधारित उद्योग लगभग उतने ही पुराने है जितनी कृषि । इस तरह के उद्योगों में न तो बहुत ज्यादा पूँजी विनियोजन की आवश्यकता होती है और न ही बहुत ज्यादा दक्ष श्रमिकों की। कृषि आधारित उद्योगों से सम्बन्धित इकाइयाँ पूरे जिले भर में कार्यरत हैं इनके लिए कच्चा माल आसानी से हर जगह सुलभ है। यह उद्योग उपभोक्ताओं के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये उद्योग माँग पर आधारित उद्योग हैं। मौसमी उच्चावचनों एवं माँग में कमी का इस उद्योग पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे इनका विकास प्रभावित होता है।

Reference:

1 Statistical handbook of Baran 2015-2016.

2 Trewartha G. T. (1969): “A Geography of Population: World Patterns”, John Willey and Sons, New York, 82.

3 United Nations (1953).Determinants and consequences of population trends. Population Studies No. 17. New York: Department of Social Affairs

4 17 Estimates and Projections. New York: United Nations.

5 Sharma, P., & Singh, R. (2019). Land Use Dynamics in Rajasthan: A Regional

6 Analysis. Journal of Environmental Management, 250, 109-119.

7 Yadav, S. (2018). Impact of Tourism on Local Communities in Ranthambore. International Journal of Sustainable Development, 27(3), 213-225.

8 Koli, Omprakash(2015). A Geographical Study level of Agricultural Development & Environmental planning in sawai madhopur District.

9 Kumar, Arun. (2017) Research paper. Changes in land use pattern: A Case